खबर संक्षेप

ई-अटेंडेंस के आधार पर होगा शिक्षकों का वेतन भुगतान, लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश जारी

छिन्दवाड़ा। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं हाई स्कूलों के संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षकों एवं विद्यालयीन अमले की उपस्थिति अब तकनीकी आधारित "हमारे शिक्षक" ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी तथा ई-अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा के लिए "हमारे शिक्षक" ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू की गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों में प्राचार्यों, शिक्षकों एवं समस्त कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज कराना सुनिश्चित करें। निर्देश में कहा गया है कि संकुल प्राचार्य ई-अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। यदि बिना ई-अटेंडेंस के वेतन आहरित किया जाता है तो इसके लिए संबंधित संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों द्वारा किसी तिथि की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं की जाएगी।

हर्रई जनपद की अमारी पंचायत का मामला, सचिव ने सरपंच पति से की अभद्रता

रिश्वत में मांगा फ्रिज और 20 हजार रुपये!

हरिभूमि न्यूज ▶▶ छिंदवाड़ा, मनीष गड़करी

जिले की जनपद पंचायत हर्रई अंतर्गत ग्राम पंचायत अमारी में पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगने और भुगतान रोकने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

आरोप है कि जनपद सदस्य निधि से स्वीकृत पुलिया निर्माण कार्य के भुगतान के एवज में पंचायत सचिव ने सरपंच से नगद राशि के साथ घरेलू उपयोग का फ्रिज भी मांगा। मांग पूरी नहीं होने पर सचिव ने न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि भुगतान रोकने की धमकी भी दे डाली।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अमारी में जनपद सदस्य निधि (जनपद स्तर) से पुलिया निर्माण कार्य कराया गया था। निर्माण कार्य में उपयोग की गई सामग्री का क्रय पंचायत स्तर पर किया गया और उसका भुगतान किया जाना था। आरोप है कि भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के लिए पंचायत सचिव चुन्नीलाल यादव द्वारा सरपंच पक्ष पर दबाव बनाया गया। सरपंच पति भागचंद धुर्वे का आरोप है कि सचिव ने भुगतान करने के बदले 20 हजार रुपये नकद और एक फ्रिज की मांग की।

बताया जा रहा है कि जब सरपंच पक्ष द्वारा फ्रिज उपलब्ध नहीं कराया गया तो सचिव का रवैया आक्रामक हो गया। आरोप है कि सचिव ने सरपंच पति के साथ अभद्रता करते हुए कहा कि वह न तो पंचायत में आएगा और न ही किसी प्रकार का भुगतान करेगा। इतना ही नहीं, कथित रूप से यह भी कहा गया कि "जो करना है कर लो, भुगतान नहीं होगा।" इस घटनाक्रम के बाद पंचायत में तनाव की स्थिति बन गई और मामला जनपद पंचायत तक पहुंच गया।

सरपंच ने की शिकायत, कार्रवाई का इंतजार

मामले को लेकर ग्राम पंचायत अमारी की सरपंच द्वारा जनपद पंचायत हर्रई में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सचिव को हटाने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। शिकायत में सचिव पर रिश्वत मांगने, पद का दुरुपयोग करने और पंचायत कार्यों में बाधा उत्पन्न करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि शिकायत किए जाने के बाद भी अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से शिकायतकर्ता पक्ष में नाराजगी बढ़ती जा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोप निराधार हैं तो जांच कर सचिव को क्लीन चिट दी जानी चाहिए और यदि आरोप सही हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन लंबे समय से मामला लंबित रहने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

भ्रष्टाचार के आरोपों से पंचायत व्यवस्था पर सवाल

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए शासन करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन यदि भुगतान के बदले रिश्वत की मांग जैसे आरोप सामने आते हैं तो यह पूरे पंचायत तंत्र की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों को ही भुगतान के लिए कथित रूप से रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाएगा तो विकास कार्य प्रभावित होंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।अब क्षेत्रवासियों की नजर जनपद पंचायत हर्रई और जिला प्रशासन पर टिकी हुई है। लोगों की मांग है कि शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाए, आरोपों की सत्यता सामने लाई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि पंचायत व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे।सवाल यह है कि शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सचिव को किसी प्रभावशाली संरक्षण का लाभ मिल रहा है, या फिर जांच प्रक्रिया जानबूझकर लंबित रखी जा रही है? इसका जवाब प्रशासन को देना होगा।

जनपद सीईओ की चुप्पी पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न जनपद पंचायत हर्रई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की भूमिका को लेकर उठ रहा है। शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने से पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि आखिर सचिव के खिलाफ जांच या कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यदि किसी सामान्य कर्मचारी पर इस तरह के आरोप लगते तो तत्काल जांच बैठा दी जाती, लेकिन यहां मामला महीनों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।

आबकारी ने 950 किलो महुआ लाहन किया बरामद

हरिभूमि न्यूज ▶▶ परासिया

अवैध मदिरा परिवहन , निर्माण , विक्रय एवं संग्रहण के खिलाफ चलाया जाए चलाए जा रहे अभियान के तहत वृत परासि या के ग्राम झिरपा ,चावल पानी एवं छिंदी आदि ग्रामों में सघन तलाशी की कार्रवाई की गई । जिसमें कुल लगभग 950 किलोग्राम लावारिस महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया । वहीं 40 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जप्त की गई । इसके साथ 16 केन बीयर मदिरा एवं 36 पाव देशी मदिरा एवं 32 पाव ऑफिसर चॉइस मदिरा बरामद किया गया ।

जप्त महुआ लाहन एवं मदिरा की कीमत 1लाख 5 हजार आंकी गई है ।बुधवार को हुई इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए । जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश होने को कहा ,बाद जमानत पर रिहा किया गया । कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी वासुदेवाचार्य त्रिपाठी , आबकारी उप निरीक्षक वृत परासिया जीत सिंह धुर्वे , आबकारी आरक्षक ओम नारायण बामने , महिला आरक्षक प्रियंका सरयाम , दीपाली झारिया एवं रवि शंकर कंगाली का सहयोग रहा ।

स्वच्छता मिशन के तहत खरीदे डस्टबिन लगने की बजाए पंचायत की बढ़ा रहे शोभा

सीसी रोड शेड निर्माण के बाद स्वच्छता मिशन में भी फर्जीवाड़ा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ तामिया

जनपद पंचायत तामिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मानकादेई इन दिनों कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक उदासीनता को लेकर चर्चा में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में पिछले दो माह के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर लाखों रुपये का आहरण किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज वित्तीय जानकारी और मौके पर दिखाई देने वाले कार्यों का मिलान करने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत में नींबूढाना में निर्मित की जा रही सीसी सड़क तथा पंचायत भवन में शेड और फर्श निर्माण कार्यों में गुणवत्ता संबंधी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि निर्माण कार्यों में मानकों की अनदेखी की गई और सामग्री की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में है। यदि इन कार्यों की तकनीकी जांच कराई जाए तो कई वित्तीय अनियमितताएं उजागर हो सकती हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत सचिव पर उच्च अधिकारियों का संरक्षण होने के कारण उनकी कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है। यही वजह है कि पंचायत में निरीक्षण व्यवस्था लगभग निष्क्रिय नजर आती है। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो पंचायत निरीक्षक नियमित रूप से निरीक्षण करने पहुंचते हैं और न ही

क्रियान्वयन को लेकर उठ रहे सवाल

वहीं, केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डस्टबिन उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन मानकादेई पंचायत में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

सामग्री के उपयोग पर लग रहे प्रश्नचिन्ह

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत द्वारा डस्टबिन की खरीदी तो की गई, लेकिन उनका उपयोग उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो रहा है। महीनों पहले खरीदे गए डस्टबिन आज भी पंचायत परिसर में रखे हुए हैं, जबकि उन्हें गांव के सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्थापित किया जाना चाहिए था। इससे न केवल स्वच्छता अभियान का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि खरीदी गई सामग्री के उपयोग पर भी प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन का ध्यान योजनाओं के प्रभावी संचालन की बजाय केवल खरीदी और भुगतान की प्रक्रिया तक सीमित रह गया है। परिणामस्वरूप स्वच्छता मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

ऑडिट के अभाव पर में पनप रही अनियमितताएं

अब सवाल यह उठता है कि यदि पंचायत में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, वित्तीय व्यय और स्वच्छता मिशन के क्रियान्वयन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। नियमित निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण और वित्तीय ऑडिट के अभाव में यदि अनियमितताएं पनप रही हैं, तो इसके लिए केवल पंचायत स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी भी जवाबदेह माने जाने चाहिए।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनपद पंचायत तामिया से मांग की है कि पंचायत में हुए निर्माण कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए खर्चों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई हो सके।

चौरई में बिजली विभाग ने किया एक दिन में तीस जगह विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज

चौरई। एमपीईबी चौरई क द्वारा बिजली चोर से 47 हजार जुर्माना भी वसूला चौरई। क्षेत्र में विद्युत चोरी के मामलों में बुधवार को विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। झिलमिली से माचागोरा सहित आधा दर्जन जगहों पर विद्युत चोरी के 30 प्रकरण दर्ज किये गए। इसके अलावा एक प्रकरण में 47 हजार 500 का जुर्माना वसूल किया गया। एमपीईबी एई अंकित जैन ने बताया कि बुधवार को क्षेत्र में विजिलेंस और विभाग की टीमों ने चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान चौरई, झिलमिली, मोहगांव, पलटवाड़ा, चीचगांव, माचागोरा सहित अन्य हैं में चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिसमें घरों और अन्य जगहों पर चोरी की बिजली का उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने यहां से प्रकरण जब्त कर आगे की कारवाई की। ठेकेदार से जुर्माना हुआ वसूल विकासखंड के पलटवाड़ा में पकड़ाई बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज होने के बाद भी ठेकेदार ने राशि जमा नहीं की थी। ऐसे में बुधवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यहां पर ठेकेदार द्वारा 47500 का जुर्माना ब्याज सहित जमा करवाया गया। बताया जाता है कि इसके पूर्व में भी विभिन्न क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा 2 जून को 29 बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज किए गए थे।

छिंदवाड़ा की बेटी का गौरवः प्रिया मालवी बनीं इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर

छिंदवाड़ा। शहर के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में, स्थानीय निवासी प्रिया मालवी का चयन भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। अपनी इस उपलब्धि से उन्होंने न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है।मेहनत और लगन का परिणामप्रिया मालवी, छिंदवाड़ा पुलिस विभाग में एएसआई (ए एस आई) के पद पर कार्यरत श्री रवि मालवी और श्रीमती उर्मिला मालवी की सुपुत्री हैं। प्रिया की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अटूट संकल्प और परिवार का निरंतर सहयोग रहा है। बचपन से ही देश सेवा का जज्बा रखने वाली प्रिया ने अपनी शिक्षा और तैयारी के दौरान कठिन परिश्रम किया, जिसका सुखद परिणाम आज उनके चयन के रूप में सामने आया है।परिवार में हर्ष का माहौलप्रिया के चयन की खबर मिलते ही उनके परिवार और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। माता-पिता ने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए अत्यंत भावुक और गौरव का पल है। उन्होंने बताया कि प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और परिवार के मार्गदर्शन को दिया है।

मानसून की पहली ही बारिश में आफतः क्षेत्र वासियों को मिली गर्मी उमस से राहत

आंधी-तूफान से तहसील कोर्ट परिसर में गिरे विशाल पेड़, वाहन क्षतिग्रस्त

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सौंसर

क्षेत्र में बुधवार शाम करीब 4 बजे मानसून की पहली झमाझम बारिश ने दस्तक दी। बारिश से जहां भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं दूसरी ओर तेज आंधी और तूफान ने जमकर कहर बरपाया।

तेज हवाओं के कारण तहसील कोर्ट परिसर में भारी नुकसान हुआ है। वर्षों पुराने दो बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़कर गिर गए, जिसकी चपेट में आने से कई वाहन चकनाचूर हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आंधी की गति इतनी तेज थी कि परिसर में खड़े पुराने पेड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय परिसर में लोगों की आवाजाही होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति पेड़ों की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। हालांकि, पेड़ों के नीचे खड़ी दो मोटरसाइकिलें और एक कार बुरी तरह दब गई, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे।

अधिकारियों ने सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र की घेराबंदी की और गिरे हुए पेड़ों को हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया। प्रशासन फिलहाल नुकसान का विस्तृत आकलन कर रहा है और प्रभावित वाहन मालिकों से जानकारी जुटाई जा रही है।आंधी-तूफान के कारण शहर के अन्य हिस्सों में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर के सभी पुराने और जर्जर पेड़ों का नियमित निरीक्षण किया जाए। लोगों का कहना है कि प्रशासन को मानसून पूर्व ही ऐसे खतरनाक पेड़ों को चिह्नित कर उन्हें कटवा देना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जनहानि न हो।

बिजली की आंख मिचोली से शहरवासी हो रहे परेशान

एक ओर जहां शहर वासी एवं ग्रामीणों को गर्मी परेशान कर रही है वहीं दूसरी और मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की ओर से की जा रही बिजली की आंख में चोली से भी आम जनमानस परेशान हो रहा है। विगत कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर रात्रि के साथ ही दिन में बिजली की आंख में चोली हो रही है, बुधवार को बारिश के बाद में भी सौसर क्षेत्र कई वार्डों में लो वोल्टेज की परेशानी एवं बिजली की आंख मिचोली से शहर वासियों को परेशान होना पड़ा है।

विशाल गौशाला के लिए जमीन की मांग, वसुंधरा संस्था ने जताई चिंता

सिंगोड़ी। सिंगोड़ी वसुंधरा शैक्षणिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था के संचालक पवन राव सोनी ने कहा कि संस्था पिछले कई वर्षों से गौशाला खोलने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। पवन राव सोनी ने बताया कि राजनेताओं और प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित करने के लिए संस्था लगातार प्रयासरत है। संस्था ने शासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि गौशाला खोलने के लिए उचित भूमि उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में संस्था श्री राम गौशाला का विधिवत संचालन कर रही है। गौशाला में 32 गोवंश मौजूद हैं। इन सभी का पालन-पोषण संस्था अपने खर्च पर कर रही है। पवन राव सोनी ने कहा कि अगर शासन जमीन उपलब्ध कराए तो बड़ी संख्या में आवारा गोवंश को संरक्षण दिया जा सकेगा और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं व मौतों पर रोक लगेगी।

वार्ड क्रमांक-5 में हाई पावर ट्रांसफार्मरों के आसपास गंदगी और अव्यवस्था

लापरवाह विद्युत विभाग, लोगों की जान से खुला खिलवाड़

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जुन्नारदेव

नगर के वार्ड क्रमांक-5 में स्थापित 200 केवीए एवं 315 केवीए क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थिति इन दिनों विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। लाखों रुपये की लागत से स्थापित इन उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के आसपास फैली गंदगी, झाड़ियां, कचरा और आवारा पशुओं की आवाजाही स्थानीय नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

क्षेत्रवासियों का आरोप है कि विद्युत विभाग मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है।स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रांसफार्मरों के आसपास लंबे समय से साफ-सफाई नहीं कराई गई है। कई स्थानों पर झाड़ियां उग आई हैं, वहीं कचरे के ढेर और अनुपयोगी सामग्री भी पड़ी हुई दिखाई देती है। सबसे गंभीर बात यह है कि इतने उच्च क्षमता वाले विद्युत उपकरणों के आसपास सुरक्षा मानकों के अनुरूप पर्याप्त घेराबंदी, चेतावनी संकेतक और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं नजर नहीं आतीं। ऐसे में बच्चों, राहगीरों तथा पशुओं के लिए हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और यदि ट्रांसफार्मरों के आसपास जलभराव जैसी स्थिति निर्मित होती है तो खतरा और बढ़ सकता है। विद्युत उपकरणों के समीप गंदगी और नमी तकनीकी खराबी के साथ-साथ बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते विभाग ने आवश्यक कदम नहीं उठाए तो किसी अप्रिय घटना से इंकार नहीं किया जा सकता।

मेंटेनेंस के दावों पर उठे सवाल

नागरिकों का आरोप है कि विद्युत विभाग नियमित निरीक्षण और रखरखाव की बात करता है, लेकिन वार्ड क्रमांक-5 की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि नियमित मेंटेनेंस किया जा रहा है तो फिर ट्रांसफार्मरों के आसपास इतनी अव्यवस्था क्यों है? लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता।

सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार 200 और 315 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मरों के आसपास पर्याप्त सुरक्षा घेरा, जालीदार बाड़, चेतावनी बोर्ड, उचित अर्थिंग व्यवस्था और नियमित तकनीकी परीक्षण अनिवार्य माने जाते हैं। लेकिन वार्ड क्रमांक-5 में इन मानकों का पालन होता नजर नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मरों के आसपास पशुओं का जमावड़ा और फैली गंदगी विभागीय लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है। क्षेत्रवासियों ने सवाल उठाया है कि जब विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तब ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर इतनी उदासीनता क्यों बरती जा रही है। नागरिकों ने विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेकर साफ-सफाई, सुरक्षा घेराबंदी तथा नियमित निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि विभाग की यह अनदेखी भविष्य में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिसकी जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है।

बड़कुही अस्पताल में शिशुओं का हो सकेगा इलाज श्रमिक संगठन एचएमएस ने उठाई थी मांग

परासिया:- वेकोलि के बड़कुही स्तिथ अस्पताल में अब गैर वेकोलि कर्मियों के बच्चों का इलाज भी हो सकेगा ।इसके लिए श्रमिक संगठन एच एम एस ने पेंच महाप्रबंधक से मांग रखी थी ।बता दें , कि परासिया में कोल्ड्रिफ सिरप कांड में शहर के कुछ शिशु रोग विशेषज्ञ आरोपी होने के कारण जेल में है ।जिसके बाद से बच्चों के इलाज की समस्या खड़ी हो गई थी ।वेकोलि के बड़कुही अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ होने के बावजूद यहां सिर्फ वेकोलि कामगारों के बच्चों का ही इलाज किए जाने की बाध्यता है , लेकिन इस मामले में श्रमिक संगठन एच एम एस ने पेंच महाप्रबंधक से यह व्यवस्था गैर वेकोलि कामगारों के बच्चों के लिए भी शुरू कर दी जाए ।जिसके बाद पेंच महाप्रबंधक ने सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को सभी बच्चों का इलाज करने के निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिए हैं । एच एम के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने इसके लिए प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए बताया है , कि सप्ताह के उक्त दो दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आम लोग भी अपने बच्चों के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ से इलाज करा सकेंगे ।

एग्रीमेंट विवाद को लेकर प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल

पीबीएम कंपनी में सैकड़ों श्रमिकों का आंदोलन जारी, अन्य यूनियनों का भी मिल रहा कामगारों को अब समर्थन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सौसर

औद्योगिक क्षेत्र की पीबीएम कंपनी के लगभग 400 कामगारों की 'काम बंद' हड़ताल बुधवार को आठवें दिन भी जारी रही। 2 जून की रात से शुरू हुआ यह आंदोलन अब विकराल रूप ले रहा है। श्रमिक अपनी एग्रीमेंट की वाजिब मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कंपनी प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों की कथित उदासीनता ने श्रमिकों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। विवाद की मुख्य जड़ एग्रीमेंट की राशि है। कामगार प्रदीप कड़ू, संजय पाटिल, नरेंद्र रगारे, भोजराज बल्कि, श्रावण सोनटक्के आदि का कहना है कि वे 3250 से 3750 की एग्रीमेंट राशि की मांग कर रहे हैं, जो उनकी मेहनत के अनुरूप वाजिब है। आरोप है कि दो स्थानीय यूनियनों ने श्रमिकों के हितों को दरकिनार करते हुए, प्रबंधन के साथ सांठगांठ कर चुपके से महज 2750 में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कदम को श्रमिकों ने अपने साथ 'धोखा' करार दिया है।

आठ दिनों से तपती धूप में डटे श्रमिकों का सवाल है कि आखिर वे किसके दबाव में पिस रहे हैं? स्थानीय प्रशासन के साथ श्रम विभाग और अधिकारी अब तक केवल चर्चा और नसीहतों तक सीमित हैं। श्रमिकों का आरोप है कि प्रशासन का यह 'मूकदर्शक' रवैया प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है। श्रमिकों ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि जिन 2 यूनियनों को उनका नेतृत्व करना चाहिए था, उन्होंने प्रबंधन से मिलकर श्रमिकों की पीठ में छुरा घोंपा है।

3 बड़ी यूनियनों का मिलेगा साथ, आंदोलन होगा और उग्र

अन्याय के खिलाफ अब श्रमिकों को नई ऊर्जा मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सौसर क्षेत्र की तीन बड़ी यूनियनों ने इन 400 कामगारों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही आंदोलन रथ कामगारों की अन्य कंपनियों में कार्य करने वाली श्रमिक यूनियनों क्षेत्र के श्रमिक नेताओ जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा एवं बैठके चल रही है। श्रमिक नेताओं ने बताया कि यदि प्रशासन प्रबंधन ने जल्द ही निष्पक्ष मध्यस्थता नहीं की और एग्रीमेंट की मांगों पर विचार नहीं किया, तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वही दूसरी ओर आठ दिनों से चल रही इस अनिश्चितता ने न केवल श्रमिकों के परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर औद्योगिक शांति को भी खतरे में डाल दिया है। फिलहाल, क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश है और सभी की नजरें जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। वहीं चुनाव के समय घर-घर में पहुंचकर वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि नेता इस आंदोलन में समाधान और कामगारों को सहयोग करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं।

निर्माण कार्य से रास्ता बंद होने की अटकलों पर लगा विराम

पिपला नारायणवार। नगर के वार्ड-13 में शासकीय स्कूल के समीप प्रस्तावित दुकानों के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंताएं अब दूर हो.ती दिख रही हैं। निर्माण से मुख्य मार्ग बंद होने की आशंका जताते हुए रहवासियों ने जहां सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, वहीं मंगलवार को नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अरुणा कैलाश चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति स्पष्ट की और नागरिकों को आश्वस्त किया कि आवागमन के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी।सोमवार को वार्ड-13 के निवासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी कि स्कूल के समीप प्रस्तावित दुकानों का निर्माण आम रास्ते को बाधित कर सकता है। नागरिकों का तर्क था कि यह मार्ग पिपला के मुख्य मार्ग को सौंसर-पांढुर्णा रोड से जोड़ता है और बस स्टैंड व एसबीआई बैंक तक जाने के लिए यह एक प्रमुख रास्ता है, जिसे बंद करने से बड़ी आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विवाद की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अरुणा कैलाश चौधरी, सीएमओ डी.पी. साहू और तकनीकी टीम ने निर्माण स्थल का मौका मुआयना किया और जमीन की पैमाइश की।स्थिति का जायजा लेने के बाद नगराध्यक्ष श्रीमती चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि मार्ग बंद होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। निर्माण के दौरान आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाएगा और रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा।उन्होंने बताया कि परिषद की बैठक में लिए गए सर्वसम्मत निर्णय के तहत पुराने स्कूल भवन के पास 3 ऊपर और 3 नीचे (कुल 6) दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।

वार्ड 10 में जुन्नारदेव में पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य का हुआ भूमिपूजन

जुन्नारदेव। नगर के वार्ड क्रमांक 10 में वार्ड वासियों की मांग के आधार पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य आगामी दिनों में प्रारंभ किया जाएगा। 205000 की लागत से लग रहे पेवर ब्लॉक का बुधवार 10 जून को विधिवत भूमि पूजन किया गया। यह पेवर ब्लॉक का कार्य सिद्धू साहू के घर से मुकेश चौरसिया के घर तक किया जाना है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, उपाध्यक्ष सोनिया कुमरे, भाजपा नेता शरद कुरोलिया, नपा कर्मचारी गणेश चौरसिया, ऋतिक एवं जॉनी पाल उपस्थित थे।

खेलकूद से मस्तिष्क और शरीर रहता है स्वस्थः सांसद साहू

छिन्दवाड़ा। खेलकूद से खिलाड़ियों का मस्तिष्क और शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। हमारे जीवन में अन्य गतिविधियों के साथ ही खेलकूद भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार द्वारा खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा हैं। छिन्दवाड़ा में भी खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है। खेल मैदानों को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों की राशि भी स्वीकृत हुई है जिससे निर्माण कार्य चल रहे है। उक्त आशय के उद्गार सांसद बंटी विवेक साहू ने ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित ग्रीष्म कालिन खेल प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन खेल और युवक कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन आज प्रशिक्षकों के सम्मान व पुरस्कार वितरण के साथ स्टेडियम हाल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप लगातार प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में मेहनत करें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का प्रयास करें। मैं उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सांसद खेल महोत्सव की रूपरेखा बनाकर आप सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बार फिर अवसर मिलेगा। इस अवसर पर सांसद श्री साहू ने खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। उन्होंने स्टेडियम ग्राउंड में बने ओपन जिम का शुभारंभ भी किया। जिला शिक्षा अधिकारी पीएल मेश्राम ने खिलाड़ियों को सतत प्रशिक्षण व अभ्यास कर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण शिविर में 2725 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी प्रशिक्षकों को विभाग द्वारा उच्च स्तरीय ट्रैकसूट प्रदान किए गए। इस अवसर पर खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु विश्वामित्र अवार्डी केआर तिवारी, नवीन बारस्कर, रोहित पोफली, रिजवान कुरैशी, विश्वेंद्र बैंस, जिला खेल अधिकारी के के चौरसिया आदि मौजदू रहे।

खाद वितरण की व्यवस्था सख्त, ई-टोकन प्रणाली से बिचौलियों पर लगेगी लगाम

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सौसर

खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों के बीच किसानों को खाद की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौसर, सिद्धार्थ पटेल ने उर्वरक भंडारण और वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए 'ई-टोकन' व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ वर्ष 2026 के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कुल 35 हजार मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 32,244 मीट्रिक टन खाद वितरित की गई थी, जिसे देखते हुए इस वर्ष मांग बढ़ने का अनुमान है।

प्रशासन ने दावा किया है कि वर्तमान में जिले में 7,282 मीट्रिक टन उर्वरक स्टॉक में उपलब्ध है, जो शुरुआती सीजन की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने स्पष्ट किया कि खाद वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ई-टोकन प्रणाली लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि ई-टोकन से वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित होगी। बिचौलियों और खाद की जमाखोरी करने वाले तत्वों पर प्रभावी रोक लगेगी। इस व्यवस्था से वितरण प्रक्रिया का रिकॉर्ड डिजिटल रहेगा, जिससे मॉनिटरिंग आसान होगी। बैठक में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एमओपी और एनपीके जैसे प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। एसडीएम श्री पटेल ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि खरीफ सीजन के दौरान खाद की किल्लत न हो, यह उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

जरूरतमंदों के भंडारे के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न

छिंदवाड़ा। लिंगा आश्रम लिंगा में अमावस्या के आसपास प्रतिमाह भंडारे का आयोजन सम्पन होता हैं । इसी कड़ी में आज आश्रम के आसपास के निवासरत जरूरत मंदों को राशन किट भेंट की गई । गत 6 वर्षों से यह सेवा निर्विवाद रूप से जारी है । जरूरतमन्दों को राशन किट भेंट कर भोजन प्रसादी भी दी जाती है । आश्रम प्रबंधक द्वारा इस बार विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया । यह शिविर नेमा क्षारसूत्र संस्थान द्वारा लगाया गया था । जिससे असाध्य बीमारियों का मुफ्त में इलाज होगा । बहुत से जरूरत मंदों का बी पी ,शुगर और हीमोग्लोबिन चेक किया । पूज्य बापूजी का यह देश का ऐसा पहला आश्रम है जहां गरीबों को निःशुल्क राशन किट के साथ प्रतिमाह उनके पुराने रोगों का इलाज भी मुफ्त होगा । स्वास्थ्य शिविर भी प्रतिमाह आयोजित होगा । इस शिविर में डॉ. पवन नेमा जी ,डॉ रश्मि नेमा और प्रसिद्ध डॉ. अरविंद राउत ने अपनी सेवाएं दी । समय समय पर नागपुर से विशेषज्ञ डॉकटरों की टीम यहाँ आकर निःशुल्क सेवा देगी ।

कलेक्टर ने ली जिला स्तरीय खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण समिति की बैठक

छिन्दवाड़ा। जिले में खेलों के विकास और खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण और उन्नयन कार्य के लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक गत दिवस आयोजित हुई। बैठक में जिले के इमलीखेड़ा क्षेत्र में निर्मित होने वाले इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए भवन निर्माण विकास निगम के अधिकारी को टेंडरिंग प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार पीआईयू को इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम और टीटी हॉल के शेष बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया।कलेक्टर ने ओलंपिक स्टेडियम में ग्रास फील्ड के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया। ओलंपिक खेल स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम के सुलभ संचालन और रख रखाव , आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक नियमावली बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी खेल संघों को स्टेडियम के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा- लोकतांत्रिक अधिकारों का हो रहा हनन, जनता की आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने पर लांजी में कांग्रेस का हल्ला बोल, भाजपा सरकार के खिलाफ गरजा विपक्ष

हरिभूमि न्यूज लांजी। मध्यप्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में लांजी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। बड़ी संख्या में एकत्रित कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओ ने नारेबाजी करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया और इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई करार दिया।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष का ऐलानः प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी के नामांकन को निरस्त कर जनता की भावनाओं और संविधान की भावना को आहत करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अन्याय और कथित तानाशाही के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेगी।

भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोपःभाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोपवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी और विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीतिक षड्यंत्र में लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका जवाब जनता समय आने पर मतदान के माध्यम से देगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संघर्ष है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाने का संकल्प लिया।

इस अवसर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ मोनू पसीने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बहेला के अध्यक्ष ऋषि पटेल दशरिया,ब्लॉक कांग्रेस कमिटी लांजी के अध्यक्ष रेवाजी करहाटकर, युवा कांग्रेस कमेटी लांजी -किरनापुर न्के अध्यक्ष मनीष हुकुमचंद जुझार सरपंच संघ लांजी के अध्यक्ष ललित कबीरे , जनपद पंचायत लांजी के सभापति दिनेश लांडे, जनपद पंचायत लांजी की अध्यक्ष अर्चना रेवेंद्र खोंगल , जनपद पंचायत लांजी के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष देवेंद्र खोंगल , पूर्व जनपद सदस्य घनश्याम पटले आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

5 लाख पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

धारा 49(6) समाप्त करने सहित 6 प्रमुख मांगें रखीं

हरिभूमि न्यूज कटंगी। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा कटंगी के पदाधिकारियों ने बुधवार 10 जून को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम कटंगी में एसडीएम के.सी.ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने ज्ञापन सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स की लंबित न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र की देय तिथि से न तो महंगाई राहत मिल रही है और न ही स्वास्थ्य लाभ, जिससे पेंशनर्स और उनके परिवारों में निराशा और असंतोष व्याप्त है। पेंशनर्स को मिलने वाले लाभ में लगातार देरी और कटौती के कारण उनका जीवन अभावग्रस्त हो गया है। ज्ञापन में 6 प्रमुख मांगें रखी गई हैं और इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र कार्रवाई की अपील की गई है। एसोसिएशन ने धारा 49(6) को समाप्त करने, कैशलेस बीमा प्रीमियम में समानता, समय पर एरियर और 06 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान, 79 वर्ष से 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ, न्यायालयीन निर्णयों का पालन, कर्मचारियों की तरह उपादान जैसी मांग शामिल है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में लिखा कि महंगाई राहत और स्वास्थ्य लाभ न मिलने से पेंशनर्स का मनोबल गिर रहा है। केंद्र सरकार की देय तिथि के अनुसार लाभ न मिलने से 5 लाख पेंशनर्स और उनके परिवार परेशान हैं। कई वृद्ध पेंशनर्स इलाज और दैनिक खर्च के लिए मोहताज हो गए है। कटंगी शाखा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार इन मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लेती तो प्रदेशभर के पेंशनर्स को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वृद्ध पेंशनर्स की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए तुरंत निराकरण किया जाए।

धारा 49(6) समाप्त हो- एसोसिएशन ने म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को अविलंब समाप्त करने की मांग की है। पेंशनर्स का कहना है कि इस धारा के कारण उन्हें लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैशलेश बीमा प्रीमियम में समानता- राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कर्मचारियों से कैशलेश बीमा योजना के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम लिया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स से 4 प्रतिशत लिया जा रहा है। एसोसिएशन ने मांग की कि पेंशनर्स से कोई प्रीमियम न लिया जाए, और यदि लिया जाए तो कर्मचारियों से अधिक न लिया जाए। समय पर एरियर और 6 प्रतिशत ब्याज- पेंशनर्स को डेथ ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट लाभ 4, 6, 8 माह बाद या 1 वर्ष बाद भी मुश्किल से मिलते हैं। एसोसिएशन ने कहा कि हक पर डाका डालना घोर अन्याय है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और अन्य न्यायालयों के निर्देशों का हवाला देते हुए मांग की गई कि कोरोना काल का एरियर, 6वें वेतनमान का 32 माह और 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान किया जाए। 79 वर्ष से 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ- पूर्व में माननीय न्यायालयों ने निर्णय दिया है कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाए। एसोसिएशन ने मांग की कि इस लाभ को 79 वर्ष पूर्ण होने पर ही दिया जाए, ताकि वृद्धावस्था में पेंशनर्स को तुरंत राहत मिल सके।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद पंचायत भवन में एफटीके प्रशिक्षण सम्पन्न

77 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जल गुणवत्ता जांच का दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) द्वारा जनपद पंचायत वारासिवनी भवन में फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यपालन यंत्री बी.एल. उइके के मार्गदर्शन में किया गया।प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपखंड वारासिवनी के सहायक यंत्री विजय तिवारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी श्रीमती यशोदा भगत की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रशिक्षण में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले झालीवाड़ा, रामपायली एवं सिकंदरा-3 सेक्टर की 77 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।

प्रशिक्षण के दौरान प्रयोगशाला केमिस्ट श्रीमती रेखा पटले एवं श्रीमती टीना बिसेन तथा ब्लॉक समन्वयक प्रतांशी पाठक ने कार्यकर्ताओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। केमिस्ट रेखा पटले ने किट के उपयोग का लाइव प्रदर्शन करते हुए बताया कि इसके माध्यम से पानी में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन, हार्डनेस, क्लोरीन तथा पीएच (pH) मान की जांच कम समय में की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दूषित पानी के सेवन से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में विभिन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए जल स्रोतों की नियमित जांच अत्यंत आवश्यक है।

परियोजना अधिकारी श्रीमती यशोदा भगत ने प्रशिक्षण के दौरान जल जीवन मिशन के तहत सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में जल स्रोतों की नियमित जांच कर उसका रिकॉर्ड तैयार करेंगी। यदि किसी जल स्रोत का पानी दूषित पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी, जिससे समय पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करना भाजपा की साजिश व लोकतंत्र की हत्या - पटेल

हरिभूमि न्यूज वारासिवनी। मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कथित रूप से हलफनामे में एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी दर्ज नहीं करने के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस ने फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उन्हें केवल न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ था। पार्टी नेताओं का कहना है कि तथ्यों की गलत व्याख्या कर नामांकन निरस्त किया गया है।

इधर, वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने मीनाक्षी नटराजनका नामांकन निरस्त किए जाने को भाजपा की साजिश और लोकतंत्र की हत्या बताते हुए इसे प्रदेश की राजनीति का काला दिन करार दिया। विधायक पटेल ने आरोप लगाया कि सत्ता प्राप्त करने के लिए सुनियोजित तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी और पार्टी के सभी विधायक एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन के साथ खड़े हैं।

विधायक श्री पटेल ने भाजपा पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है और कांग्रेस इस मामले को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।

आस्था पर हमला! सिद्धपीठ गांगजी राजा मंदिर में चोरों का तांडव, दान पेटी तोड़ लाखों की नकदी उड़ाई

मान्यता के के सैकड़ों नारियल जलाए, आग की चपेट में आई देव प्रतिमाएं, घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश

हरिभूमि न्यूज लांजी। लांजी थाना क्षेत्र की सुलसुली चौकी अंतर्गत ग्राम चौरिया चिलौरा स्थित प्राचीन सिद्धपीठ गांगलीराजा मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा की गई चोरी और आगजनी की घटना ने पूरे क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है। रात के अंधेरे में मंदिर पहुंचे अज्ञात बदमाशों ने न केवल दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखी करीब डेढ़ से दो लाख रुपये तक की नकदी पर हाथ साफ किया, बल्कि श्रद्धालुओं द्वारा मान्यता पूरी होने पर बांधे गए लगभग 400 मानता के नारियलों को भी आग के हवाले कर दिया। इस आग की चपेट में मंदिर परिसर में स्थापित देव प्रतिमाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

आपको बता दे कि गांगलीराजा मंदिर वर्षों पुराना सिद्धपीठ स्थल है, जहां मध्यप्रदेश सहित महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुंचते हैं। शारदीय नवरात्रि के पश्चात यहां विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन प्रारंभ हो जाते हैं, जो बारिश के मौसम तक चलते हैं। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस पवित्र स्थल पर हुई घटना से क्षेत्र में रोष और दुख का माहौल है। क्षेत्र में यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी लांजी थाना क्षेत्र के बोलेगांव, मोहझरी, भानेगांव सहित कई गांवों के मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही इन वारदातों ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना की सूचना मिलते ही लांजी थाना प्रभारी दीपसिंह परमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की तथा अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जांच कर रही है। वहीं श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

खबर संक्षेप

भोमा गांव के यश चंद्रवंशी ने नेपाल की 100 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक

हरिभूमि न्यूज सिवनी। जिले के भौमा गांव निवासी युवा धावक यश चंद्रवंशी ने बेहतरीन खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में 12वीं कक्षा पास करने वाले यश ने नेपाल में 7 से 9 जून तक आल इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन (एआइएसएफ) द्वारा आयोजित इंटरनेशनल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2026 की 100 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सोमवार को 100 मीटर दौड़ में भाग लेकर यश चंद्रवंशी ने मात्र 11.02 सेकंड के समय में इसे पूरा कर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। सिवनी-मंडला मार्ग पर स्थित भौमा गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक के साथ भोमा के यश चंद्रवंशी। भारत का परचम लहराने वाले यश की इस उपलब्धि से परिवार, गांव व जिले में हर्ष का माहौल है।

जिला चिकित्सालय में चलाई जा रही नारायण सेवा

हरिभूमि न्यूज सिवनी। नित्य नारायण सेवा जो जिला चिकित्सालय सिवनी में चलाईं जा रही है इसमें सभी का सहयोग मिल रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ आये अटेण्डर की आवश्यकता को देखते हुए, उनके भोजन पैकेट की व्यवस्था करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जिसमें श्री सत्य साई सेवा समिति के माध्यम से पिछले एक वर्ष 29 जून 2025 से लगातार बिना रुकावट के प्रतिदिन संचालित हो रही है माह की प्रत्येक तिथि और दिन ग्रामवार आवंटित कर दिये गये हैं जिसके अनुसार ग्रामवासी स्वयं घरों से फुड पैकेट कलेक्ट कर नियमानुसार प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच जिला चिकित्सालय सिवनी पहुचाते हैं जहाँ पहले से उपस्थित सेवा दल के सदस्य विधिवत श्री सत्य साई सेवा समिति के बैनर तले सुसज्जित टेबल में पैकेटों को जमाकर वैदिक मंत्रों के साथ कतारबद्ध लगे जरूरतमंद लोगों को बड़े प्रेम से बांटते हैं जानकारी के अनुसार 31 मई 2026तक 40196 फुड पैकेट जो 21275 परिवारों के सहयोग से 2400 पुरुष सेवा दल एवं 260 महिला सेवा दल के हाथ से वितरित किए गए हैं। आगामी 28 जून को योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर एक व्रहद कार्यक्रम कर सेवा भगवान् को समर्पित की जाएगी एवं स्वामी से प्रार्थना करेंगे कि यह जनहितकारी योजना उनके आशीर्वाद से अनवरत चलती रहे।

केदारपुर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला नया नेतृत्व, परसराम उईके के चयन से कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर

सिवनी। जिले के केदारपुर क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को एक सशक्त, कर्मठ और जनप्रिय नेतृत्व प्राप्त हुआ है। पार्टी के जिला कार्यालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार युवा समाजसेवी एवं सक्रिय कार्यकर्ता परसराम उईके को प्रथक ब्लॉक केदारपुर अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं क्षेत्रीय नागरिकों में हर्ष और उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला नेतृत्व ने परसराम उईके की संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और जनसेवा की भावना को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण वे क्षेत्र में एक लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं। पार्टी को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा गांव-गांव तक पार्टी की विचारधारा पहुंचेगी।

यू एस बीज सीडस कंपनी पर कठोर कार्यवाही की उठी मांग, सौंपा ज्ञापन

माता सीता पर कथित अभद्र टिप्पणी से भड़का हिंदू समाज, यू.एस. सीड्स कंपनी के बहिष्कार और एंकर संदीप तिवारी पर FIR की मांग

राकेश अगरवार। हरिभूमि बरघाट। कुछ विगत दिवस बरघाट तहसील के स्टेडियम मैदान में आयोजित प्रगति उत्सव 362 धान बीज कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन कर रहे एंकर संदीप तिवारी द्वारा माता सीता एवं भगवान श्रीराम को लेकर कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज, भाजपा पदाधिकारियों, कृषि बीज प्रतिष्ठान संगठन तथा नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर बरघाट थाने में ज्ञापन सौंपते हुए एंकर संदीप तिवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने एवं कार्यक्रम आयोजक यू.एस. सीड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है, प्राप्त जानकारी के अनुसार 06 जून 2026 को बरघाट तहसील कार्यालय के समीप स्थित स्टेडियम मैदान में यू.एस. सीड्स इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा किसानों के लिए ₹प्रगति उत्सव 362 धान बीज₹ कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

उक्त कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन एवं सूफी गायिका शहनाज अख्तर की प्रस्तुति भी रखी गई थी। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे,प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन कर रहे संदीप तिवारी ने माता सीता को लेकर कथित रूप से व्यंग्यात्मक और आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ता बंटी पटले ने तत्काल विरोध दर्ज कराया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और चर्चाएं तेजी से वायरल होने लगीं, जिसके बाद सनातन समाज में नाराजगी फैल गई।

सामूहिक ज्ञापन में लगाए गए गंभीर आरोप

विश्व हिंदू परिषद द्वारा बरघाट थाना प्रभारी एवं प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कार्यक्रम के मंच से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला वक्तव्य दिया गया है, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में आयोजक कंपनी एवं मंच संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है, ज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि धार्मिक आस्था के प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी कर समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया है, इसलिए दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

विश्व हिंदू परिषद, भाजपा पदाधिकारियों, कृषि बीज व्यापारियों और हिंदू संगठनों ने बरघाट थाने पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, कंपनी पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग

अनुमति पत्र की शर्तों पर भी उठे सवाल

कार्यक्रम के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) बरघाट द्वारा जारी अनुमति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होगा तथा किसी भी समुदाय, धर्म अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधि नहीं की जाएगी, अनुमति आदेश में यह भी शर्त थी कि कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि नहीं होगी तथा आयोजक सभी परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी होंगे। अब हिंदू संगठनों का आरोप है कि यदि मंच से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी हुई है तो यह अनुमति की शर्तों का उल्लंघन है और इसके लिए आयोजक संस्था की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

बीज यू.एस. सीड्स कंपनी पर प्रतिबंध की मांग

ज्ञापन में शासन एवं प्रशासन से मांग की गई है कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक यू.एस. सीड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की गतिविधियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही कृषि व्यापारियों से कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील भी की गई है। हिंदू संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

कठोर कार्यवाही सहित रखी गई मुख्य मांगें

एंकर संदीप तिवारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई हो। कार्यक्रम की अनुमति शर्तों के उल्लंघन की जांच हो। आयोजक यू.एस. सीड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की भूमिका की जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर कंपनी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए। फिलहाल पूरा मामला जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग के केंद्र में है तथा बरघाट क्षेत्र में यह विषय चर्चा का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल प्रशासन ने अबतक उक्त घटना क्रम होने बाद अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो आगे भी संशय बना हुआ है।

मां बंजारी में गहराया जल संकट 15 दिनों से बंद पड़ा नलकूप

सोनखार। भीषण गर्मी के बीच मां बंजारी (उगली-केवलारी रोड) क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से नलकूप बंद पड़ा होने से जल संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित विभाग को शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक सुधार कार्य नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह नलकूप न केवल स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत है, बल्कि आसपास रहने वाले सैकड़ों वन्य प्राणी, विशेषकर बंदर भी इसी जल स्रोत पर निर्भर हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि वन क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद वन्य जीवों की पेयजल व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है

भैरोगंज से पीजी कॉलेज तक सड़क बनी परेशानी का सबब

जगह-जगह गड्ढों से बढ़ी मुसीबत, राहगीरों और विद्यार्थियों को हो रही परेशानी

भैरोगंज क्षेत्र से पीजी कॉलेज तक जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर क्षेत्रवासियों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। वर्षों पहले निर्मित यह सीसी सड़क अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिवनी।

क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से सड़क के नवनिर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।यह मार्ग शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा होने के कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी एवं आम नागरिक आवागमन करते हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण साइकिल और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है। गड्ढों से बचते हुए वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालक अक्सर असंतुलित हो जाते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार छोटे-बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क सुधार के लिए कोई प्रभावी पहल नहीं की गई।क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिले। लोगों का कहना है कि शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल होने के बावजूद इस सड़क की लगातार उपेक्षा की जा रही है।क्षेत्रीय नागरिक दिनेश ठाकुर, महेन्द्र मिश्रा, सुनील अग्रवाल, कुलदीप ठाकुर, विकास अग्रवाल, मंगल बघेल, राजेन्द्र चंद्रवंशी, मुकेश दुबे, जितेन्द्र बघेल सहित अन्य नागरिकों ने नगर पालिका परिषद से मांग की है कि भैरोगंज से पीजी कॉलेज तक की जर्जर सड़क का शीघ्र नवनिर्माण कराया जाए, ताकि आमजन और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो वे जनहित में आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।

हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिवनी।

सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र के डुंगरिया गांव स्थित हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हो गया। अज्ञात चोरों ने मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा पर चढ़ा मुकुट चुरा लिया। घटना का पता मंगलवार रात तब चला, जब मंदिर के पट बंद करने पहुंचे पुजारी ने मुकुट गायब देखा।

डुंगरिया का हनुमान मंदिर ग्रामीणों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंगलवार रात मंदिर परिसर सामान्य रूप से बंद किया गया था। रात में जब पुजारी ने भगवान की प्रतिमा पर चांदी का मुकुट नहीं देखा, तो ग्रामीणों को इसकी सूचना दी गई। लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में जमा हो गई घटना की सूचना मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ मंदिर परिसर में जमा हो गई। धार्मिक स्थल से चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और चोरी हुए मुकुट की बरामदगी की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर में वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा भेंट किए गए आभूषण सुरक्षित रखे जाते थे, लेकिन इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मामले की सूचना छपारा थाना पुलिस को दी गई।

सीसीटीवी कैमरों की खंगाल रही पुलिस- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। चोरी की घटना से जुड़े संभावित सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में प्रवेश कर मुकुट चोरी किए जाने की आशंका है। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। इस बीच, ग्रामीणों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और रात्रिकालीन निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

बैनगंगा नदी में डूबने से किसान की मौत

सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र में बैनगंगा नदी में डूबने से किसान की मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे सरेखा कला संगम घाट पर पिंडदान कार्यक्रम के दौरान हुई। देर रात तक चले खोज अभियान के बाद शव नदी से बाहर निकाला गया।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ सिवनी।

मृतक की पहचान ग्राम रेचना निवासी मोहरसिंह राणा (50) के रूप में हुई है। वे अपने परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के साथ ग्राम दुरैन्दा निवासी अपनी नानी स्वर्गीय उमनबाई का पिंडदान करने सरेखा कला संगम घाट पहुंचे थे।

नहाते समय गहरे पानी में चले गए किसान- धार्मिक अनुष्ठान और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार के सदस्य बैनगंगा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान किसान गहरे पानी में चले गए और डूब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहरसिंह को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। हालांकि, नदी के गहरे पानी और तेज बहावके कारण वे कुछ ही क्षणों में पानी में समा गए। घटना के बाद परिजनों ने तत्काल उगली थाना पुलिस को सूचना दी।चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग

सूचना मिलते ही उगली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय प्रशासन की सहायता से खोजबीन शुरू की गई। नदी में नाव चालकों और अनुभवी गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद देर रात किसान का शव नदी से बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उगली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी के गहरे क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

टैंकर से पानी वितरण करने वाले बने जनमानस के सारथी

हरिभूमि न्यूज़ आदेगाव विमल कुमार चौबे

सिवनी जिले की आदेगांव ग्राम पंचायत में पानी की कमी की समस्या बनी है ग्राम पंचायत ने भी टैंकर मोहल्ले तक पहुंचने का काम चालू कर दिया गया है परंतु टैंकर वाले आज के असली हीरो हैं। जहां सरकारी लाइन नहीं पहुंची, वहां इन्हीं की वजह से पानी पहुंचने पर चूल्हा जल रहा है, कपड़े धुल रहे हैं लोग स्वच्छ और साफ रह पा रहे हैं।

जल योद्धा टैंकर चालकों को सलाम, अपना काम छोड़कर जनसेवा

आदेगांव में चल रहे जितने भी टैंकर हैं, वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे. कई ड्राइवर अपना खेती-किसानी का काम छोड़कर सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक पानी बांट रहे हैं. गर्मी में पंचायती बोरवेल मैं पानी कम होने पर पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा इस वक्त इन्हीं टैंकरों ने पूरे गांव की प्यास बुझाई.

गली छोटी हो या रास्ता खराब, टैंकर वाले मना नहीं करते. बुजुर्गों के घर खुद पाइप पकडक़र टंकी भरते हैं. त्योहार-शादी में एक्स्ट्रा चक्कर लगाते हैं ताकि किसी की खुशी पानी की कमी से फीकी न पड़े।

आपदा में सबसे पहले

विगत कुछ दिनों से जब पानी की कीमत मची है तब से अभी तक 8 टैंकरों ने मिलकर दिन-रात एक कर दिया. स्कूल, मंदिर, हर घर में पानी पहुंचाया. आदेगांव के टैंकर भाइयों से अपील आप जो कर रहे हैं वो पुण्य का काम है. अगर सभी टैंकर वाले मिलकर एक और नया कदम उठाए की जिन जो लोग 500 रुपए नहीं दे सकते कम से कम पैसे में ही सही पर लोगों तक पानी पहुंचाएं जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। पानी बचाएं, जिससे टैंकर वालों के फेरे कम लगें.

जनवरी में टेंडर होने के बाद भी कार्य नहीं करने दे रहे स्थानीय निवासी

बाढ़ आपदा नियंत्रण के तहत बनने वाली नाली निर्माण में आपत्ति ले रहे लोग

छपारा। नगर के महाराणा प्रताप वॉर्ड स्थित हाईवे कॉलोनी,महाराणा प्रताप कॉलोनी सहित जामा मस्जिद क्षेत्र में बारिश के दिनो में होने वाली जलप्लावन की स्थिति से निपटने के लिए नगर परिषद छपारा द्वारा बाढ़ आपदा नियंत्रण के तहत छोटी नाली को तोडक़र 58 लाख की लागत से बड़ा पक्का नाला बनाने की कवायद की जा रही है जिसको लेकर परिषद द्वारा विधिवत ठेका निकाला गया साथ ही जिसका इसी वर्ष जनवरी फरवरी माह में वॉर्ड पार्षद के साथ भूमि पूजन भी किया गया किंतु 8 जून दिन मंगलवार को जामा मस्जिद क्षेत्र के लोगों द्वारा उक्त निर्माण कार्य में आपत्ति लगाने के बाद एक बार फिर उक्त काम खटाई में पड़ गया जिससे इस बार फिर बारिश में जल भराव से इस क्षेत्र को कोई नहीं बचा सकता। ज्ञात हो कि छपारा नगर के वार्ड नंबर 12 हाईवे कॉलोनी, महाराणा प्रताप और जामा मस्जिद क्षेत्र में कई वर्षों से बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति बनती है जिससे क्षेत्र के कई मकानों में बारिश का गंदा पानी,गंदगी भर जाती हैं जिसको लेकर वॉर्ड वासियों द्वारा वर्षों से इस समस्या का समाधान हेतु मांग की जा रही है,जिस पर नगर परिषद छपारा द्वारा बाढ़ आपदा नियंत्रण के तहत प्रस्ताव लेकर विधिवत इसका ठेका निकाला गया था। भूमि पूजन के बाद स्थानीय जामा मस्जिद क्षेत्र के लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि निर्माण कार्य नहीं करने देंगे जिस पर नगर परिषद ने राजस्व विभाग से जमीनी स्तर पर जांच कराई मौके पर तहसीलदार छपारा सहित परिषद अध्यक्ष, सीएमओ, परिषद के उपयंत्री सभी पहुंचे, लोगों की समस्या का समाधान हेतु वहीं इन सब मामले की जानकारी लखनादौन एस डीएम को भी दी गई उन्होंने भी स्थल निरीक्षण किया इसके बाद 8 जून को निर्माण कार्य शुरू किया गया जिसका एक बार फिर स्थानीय लोगों द्वारा फिर विरोध करना, यह अपने आप में पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा प्रतीत हो रहा हैं चूंकि बारिश अब बिल्कुल नजदीक है और यदि इस पक्के नाले का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो तीन से चार कॉलोनी में पानी भरना तय है, जिसका खामियाजा खुद यहां के बाशिंदों को भुगतना पड़ेगा। वहीं उक्त स्थान पर भू स्वामी के द्वारा आपत्ति जताई गई और वर्तमान में उक्त कार्य रुकवा दिया गया है जिसे लेकर क्षेत्रीय वासियों द्वारा जन अपेक्षा की जा रही है कि नगर के महाराणा प्रताप कालोनी, हनुमान कालोनी, हाईवे कालोनी, चौरसिया कालोनी सहित जामा मस्जिद कालोनी निवासियों की हित में नगर परिषद छपारा द्वारा उक्त जल निकासी व्यवस्था नाली निर्माण कार्य जिससे व्यवस्थित रूप से किए जाने वाले कार्य में सहयोग प्रदान किए जाने की अपील कि है। ज्ञात हो कि विगत 27 जनवरी 2025 को वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों ने नगर परिषद छपारा कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा और जनता मांग की है कि प्रति वर्ष वार्ड में तबाही मचाने वाले बरसात के पानी का उचित एवं स्थाई समाधान किया जाए। जिसको लेकर उक्त पक्के नाले निर्माण कार्य किया जा रहा था।

इश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमति शोभा ठाकुर बेवा मनोहर सिंह ठाकुर निवासी महावीर वार्ड सिवनी द्वारा अपने पति मनोहर सिंह ठाकुर के भाई पंचमसिंह ठाकुर की दिनांक 21.03.2014 को मृत्यू हो जाने से मृत्यू प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15.06.2026 को नियत है।

अत: उपरोक्त मृतक का मृत्यू प्रमाण पत्र जारी किये जाने में जिस किसी व्यक्ति या पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो वह पेशी दिनांक 15.06.2026 को या इसके पूर्व अपनी आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकता है। समयावधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यदि नियत दिनांक को अवकाश घोषित होता है तो प्रकरण में सुनवाई आगामी न्यायालयीन कार्य दिवस में की जावेगी।

आज दिनांक- 08.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी।

न्यायालय तहसीलदार सिवनी
नगरीय जिला सिवनी (म.प्र.)

सीएमओ पर लगाए जानकारी न देने के आरोप, पार्षद का यह हाल, जनता का क्या होगा

भाजपा पार्षद मनीषा कोचर ने विशेष बैठक का किया बहिष्कार

हरिभूमि न्यूज कटंगी।

नगर परिषद की कार्यशैली और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए वार्ड क्रमांक 14 की पार्षद और सभापति मनीषा कोचर ने बुधवार 10 जून को अध्यक्ष के नाम पत्र लिखकर नगर परिषद में होने वाले विशेष सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि मनीषा कोचर न सिर्फ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि नगर परिषद में सभापति का पद संभाल रही हैं और सत्ताधारी दल भाजपा की स्थानीय लीडर भी हैं। बावजूद इसके उन्हें आवश्यक जानकारी नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने बैठक से किनारा कर लिया। पार्षद मनीषा कोचर ने 10 जून बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में अध्यक्ष को संबोधित पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से उन्होंने आज होने वाली विशेष बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट कर दिया। पार्षद ने लिखा कि सीएमओ कार्यालय द्वारा उन्हें नगर परिषद से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। बार-बार मांग करने के बाद भी फाइलें नहीं दिखाई जा रहीं और लिखित जवाब टाल दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी दल की पार्षद और सभापति होने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आम जनता और विपक्षी पार्षदों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पार्षद ने इसे जनप्रतिनिधि की उपेक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात बताया।

शिक्षा उपकर और पेट्रोल-डीजल का ब्यौरा मांगा था

बहिष्कार की वजह बताते हुए मनीषा कोचर ने कहा कि उन्होंने सीएमओ से कई बार शिक्षा उपकर की वसूली और उसके खर्च का पूरा लेखा-जोखा मांगा था। शिक्षा उपकर सीधे नागरिकों से वसूला जाता है और इसका उपयोग शिक्षा के विकास में होना चाहिए। साथ ही नगर परिषद के वाहनों, जेसीबी और अन्य मशीनों में पेट्रोल-डीजल की खपत, मासिक खरीद और व्यय का ब्यौरा भी मांगा था। पार्षद का आरोप है कि इन जानकारियों के लिए उन्होंने मौखिक और लिखित दोनों रूप में आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि बिना जानकारी के बैठक में शामिल होकर केवल खानापूर्ति करना जनता के साथ धोखा होगा। इसी से आहत होकर उन्होंने विशेष सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। फिलहाल मनीषा कोचर के बहिष्कार ने नगर परिषद कटंगी में पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा एक बार फिर गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन पार्षद की मांग मानता है या यह विवाद और गहराता है।

ई-अटेंडेंस के आधार पर होगा शिक्षकों का वेतन भुगतान, अनुपस्थिति पर कटेगा वेतन

बालाघाट। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का वेतन अब ₹हमारे शिक्षक₹ ऐप के माध्यम से दर्ज की गई ई-अटेंडेंस के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। अब सभी शासकीय विद्यालयों में प्राचार्य, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य होगा।

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कांग्रेसियों ने कहा लोकतंत्र की हत्या

हरिभूमि न्यूज बालाघाट। बालाघाट में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को काली पुतली चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में करीब 50 कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राज्यसभा की सीट 'चोरी' की है और यह सीधे तौर पर 'लोकतंत्र की हत्या' है।

प्रदर्शन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राटसिंह सरस्वार ने सीधे तौर पर भाजपा पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तानाशाही रवैये की निंदा करती है।

सरस्वार ने दावा किया कि भाजपा ने कांग्रेस को अपनी बात रखने या सुनवाई का कोई मौका ही नहीं दिया। इससे साफ होता है कि बहुमत न होने के बावजूद, भाजपा ने जानबूझकर तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा और कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश रची, जिसमें वे कामयाब रहे।

शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी भाजपा को घेरते हुए 'वोट चोरी' और 'लोकतंत्र की हत्या' के आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि महज एक छोटी और मामूली आपत्ति के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया गया, जो संविधान का गला घोंटने जैसा है।

पंजवानी ने आगे कहा कि भाजपा की इस मनमानी को देश की जनता बेहद करीब से देख रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि नीट परीक्षा में धांधली, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिला हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों से परेशान जनता ही आने वाले समय में भाजपा के इस 'घमंड' को चकनाचूर करेगी।

नवीन विश्वेश्वरैया भवन में संचालित होंगे 9 शासकीय कार्यालय

पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत तैयार हुआ आधुनिक तीन मंजिला भवन, आमजन को मिलेगी बेहतर सुविधा

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

जिले में शासकीय कार्यालयों को बेहतर अधोसंरचना एवं नागरिकों को सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत निर्मित नवीन विश्वेश्वरैया भवन अब विभिन्न विभागों के कार्यालयों का नया केंद्र बनने जा रहा है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एवं पुराने आरटीओ कार्यालय परिसर में निर्मित यह आधुनिक तीन मंजिला भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसमें विभिन्न विभागों के कुल 09 शासकीय कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा रहा है।

जिला प्रशासन के अनुसार वर्तमान में इनमें से कई कार्यालय जिला पंचायत के पुराने भवन, निजी भवनों तथा अन्य स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। अलग-अलग स्थानों पर कार्यालय संचालित होने के कारण आम नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए कई जगहों पर जाना पड़ता था। नवीन भवन में इन कार्यालयों के एकीकृत संचालन से नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी।

इन विभागों के कार्यालय होंगे संचालित: नवीन विश्वेश्वरैया भवन में लोक निर्माण विभाग (सेतु संभाग), लोक निर्माण विभाग (भवन संभाग), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई क्रमांक-01, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इकाई क्रमांक-02, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रयोगशाला (लेबोरेटरी), जिला रोजगार कार्यालय, बाल विकास परियोजना (शहरी) कार्यालय, वाणिज्यिक कर कार्यालय एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (नगर तथा ग्राम निवेश) कार्यालय स्थानांतरित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग सहित कुछ कार्यालयों का नवीन भवन में संचालन प्रारंभ भी हो चुका है तथा शेष कार्यालयों का स्थानांतरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है भवन: विश्वेश्वरैया भवन को आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। विशाल कक्षों, बेहतर बैठक व्यवस्था, पर्याप्त पार्किंग, सुगम आवागमन और नागरिक सुविधाओं से युक्त यह भवन प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने में सहायक होगा। भवन का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके तथा कार्यों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

आमजन को होगा सीधा लाभ: एक ही परिसर में कई महत्वपूर्ण कार्यालयों के संचालित होने से नागरिकों को अपने कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। रोजगार, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, बाल विकास, कराधान एवं नगर नियोजन जैसे विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के लिए लोगों को एक ही भवन में सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस व्यवस्था से न केवल आमजन के समय और श्रम की बचत होगी, बल्कि विभागीय कार्यों में भी अधिक पारदर्शिता, समन्वय और दक्षता आएगी। साथ ही कार्यालयों के लिए बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होने से प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगी नई गति: नवीन विश्वेश्वरैया भवन का संचालन शुरू होने के साथ ही जिले की प्रशासनिक अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी। पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत निर्मित यह भवन प्रशासनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, शासकीय कार्यालयों के सुव्यवस्थित संचालन और नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जिले के नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि एकीकृत कार्यालय व्यवस्था से शासकीय सेवाओं तक पहुंच और अधिक आसान तथा प्रभावी बनेगी।

महर्षि विद्या मंदिर बालाघाट में तीन दिवसीय इन-हाउस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उत्साहपूर्वक समापन

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

महर्षि विद्या मंदिर, बालाघाट में आयोजित तीन दिवसीय इन-हाउस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन विद्यालय की परंपरा के अनुरूप गुरुपूजन, भावातीत ध्यान एवं भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम के सामूहिक अभ्यास के साथ उत्साहपूर्ण एवं आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने पूर्ण समर्पण, सक्रिय सहभागिता एवं उत्साह के साथ विभिन्न सत्रों में भाग लेकर अपने ज्ञान एवं कौशल का विकास किया।समापन दिवस के प्रारंभ में श्रीमती प्रेरणा जेमी ने प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस की गतिविधियों एवं प्रमुख निष्कर्षों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान हुए विविध शैक्षणिक सत्रों, शिक्षकों की सहभागिता तथा प्राप्त अनुभवों का सारगर्भित विवरण देते हुए सभी प्रतिभागियों को नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एवं आमंत्रित रिसोर्स पर्सन जयकुमार पिल्लई ने "कम्प्यूटेशनल थिंकिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" विषय पर अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों, उदाहरणों, संवादात्मक अभ्यासों एवं व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी, आनंददायी एवं छात्र-केंद्रित बनाने के उपाय साझा किए। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल तकनीकों का प्रभावी उपयोग शिक्षण की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकता है। उनके सत्र में शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अनेक नवाचारी शिक्षण तकनीकों एवं आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों की जानकारी प्राप्त की।इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य एवं वेन्यू डायरेक्टर सतीश कुमार चौरसिया ने जयकुमार पिल्लई का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि सतत व्यावसायिक विकास के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास को सुदृढ़ करते हैं तथा विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम के दौरान भावातीत ध्यान शिक्षिका सुनीता तिवारी ने भावातीत ध्यान एवं भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों को इसके विभिन्न आयामों से पुनः परिचित कराया। उन्होंने प्रतिभागियों से उनके व्यक्तिगत अनुभव साझा कराए तथा महर्षि महेश योगी जी के आदर्शों एवं भावातीत ध्यान की उपयोगिता को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने का आह्वान किया।

उर्वरक के अवैध विक्रय, भंडारण और कालाबाजारी की सूचना देने पर मिलेगा एक हजार रूपये का इनाम

सूचना दाता प्रोत्साहन योजना लागू

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

प्रदेश में कृषि व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और किसानों को असली व गुणवत्तापूर्ण खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्रदेश में ₹सूचना दाता प्रोत्साहन योजना₹ लागू की गई है। इस योजना के तहत उर्वरक के अवैध विक्रय, भंडारण, कालाबाजारी और नकली या मिलावटी खाद बनाने वालों की सही जानकारी देने वाले सजग नागरिक को सरकार द्वारा 1000 रूपये की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।उप संचालक कृषि, श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, नकली व मिलावटी उर्वरकों के निर्माण को रोकना और नियम विरुद्ध काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना है। इस योजना का लाभ प्रदेश का कोई भी नागरिक, किसान या व्यापारी उठा सकता है।

इन अवैध गतिविधियों की सूचना देने पर मिलेगा इनाम: उप संचालक कृषि ने बताया कि सूचना दाता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिना लाइसेंस के अवैध उर्वरक का विक्रय या निर्माण करने, निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में खाद का अवैध भंडारण, तय कीमतों से अधिक ऊंचे दामों पर खाद का विक्रय (कालाबाजारी) करने,नकली अथवा अमानक या मिलावटी उर्वरकों का निर्माण एवं उनकी बिक्री,सरकारी अनुदान वाले उर्वरकों (जैसे यूरिया आदि) का फैक्ट्रियों या औद्योगिक संस्थानों में अवैध उपयोग तथा अनाधिकृत रूप से उर्वरकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवैध परिवहन करने जैसी गतिविधियों की सूचना देने पर सूचना दाता को इनाम दिया जायेगा।

पहचान रहेगी गोपनीय: उप संचालक कृषि ने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति (सूचना दाता) की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और बिना उसकी अनुमति के किसी भी स्तर पर पहचान उजागर नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक सीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 पर कॉल करके इसकी गोपनीय सूचना दे सकता है। हेल्पलाइन पर प्राप्त जानकारी को सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर के पास स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे तत्काल जांच दल गठित कर त्वरित कार्रवाई की जा सके। सूचना देते समय अवैध गतिविधि का स्थान, समय और संबंधित व्यक्ति या संस्था का नाम बताना होगा। यदि संभव हो, तो साक्ष्य के रूप में फोटो, वीडियो या दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

उप संचालक कृषि के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा गठित विशेष टीम जिसमें उर्वरक निरीक्षक शामिल होंगे द्वारा जांच किए जाने पर यदि सूचना सही पाई जाती है और अवैध सामग्री की जब्ती या दोष सिद्धि होती है, तो कार्रवाई के बाद प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनादाता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यह योजना 30 सितंबर 2026 तक पूरे मध्य प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू रहेगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने सभी नागरिकों और किसान भाइयों से अपील की है कि वे कृषि क्षेत्र में सुधार और कालाबाजारी को रोकने के लिए इस योजना में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाएं।

कृषि विभाग ने धरती माता बचाओ अभियान के तहत किसानों को किया जागरूक

बालाघाट। खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल खेती की तकनीकों से अवगत कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत बिरसोला एवं बोट्टा (ह.) में कृषि विभाग द्वारा कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विस्तार अधिकारी सुश्री आंचल खोब्रागड़े ने किसानों को धान की डीएसआर (डायरेक्ट सीडेड राइस) पद्धति से बुवाई के लाभों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएसआर तकनीक से धान की खेती में श्रम, समय और पानी की बचत होती है तथा उत्पादन लागत में भी कमी आती है। यह पद्धति वर्तमान समय में जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इस दौरान किसानों को सुपर सीडर मशीन की उपयोगिता के बारे में भी विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर के माध्यम से फसल अवशेषों का प्रबंधन करते हुए सीधे बुवाई की जा सकती है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है।

भाजपा सरकार के दबाव में षड्यंत्रपूर्वक मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया गया : विधायक मधु भगत

हरिभूमि न्यूज बालाघाट।

मध्यप्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस नाटकीय घटनाक्रम के बीच निरस्त किया गया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजधानी भोपाल में उपवास एवं धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के अनेक विधायक, वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।

विधायक मधु भगत ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दबाव में चुनाव आयोग द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

श्री भगत ने कहा कि भाजपा को पहले से यह आभास था कि उसका तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएगा। इसी आशंका के चलते सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन निरस्त कराने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को ताक पर रख दिया है, जो अत्यंत निंदनीय है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि जिस आधार पर नामांकन निरस्त किया गया, वह इतना गंभीर नहीं था कि उम्मीदवार को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। इसके बावजूद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई कई संदेहों को जन्म देती है।

मधु भगत ने भाजपा की नारी सम्मान संबंधी नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक ओर भाजपा महिला सशक्तिकरण और नारी वंदन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सत्ता के लालच में एक महिला उम्मीदवार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर अपनी संकीर्ण और अवसरवादी मानसिकता का परिचय दे रही है। यह दोहरा चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी और जनता के बीच जाकर पूरी सच्चाई रखेगी। कांग्रेस का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

उपवास कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में हुई इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस मामले में न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस प्रदेशभर में व्यापक जनआंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी। विधायक मधु भगत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे।